



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2025

आश्विन 25, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9

संख्या 1735/पन्द्रह-9-2025

लखनऊ, 17 अक्टूबर, 2025

अधिसूचना

प0आ10-175

चूँकि सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सहायिकियां, प्रसुविधायें और सेवायें प्राप्त करने में लोगों को समर्थ बनाने हेतु पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या के उपयोग से, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, प्रक्रियायें सुगम हो जाती हैं और पारदर्शिता एवं दक्षता में अभिवृद्धि होती है;

और, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार (जिसे आगे उक्त सरकार कहा गया है) में माध्यमिक शिक्षा विभाग (जिसे आगे विभाग कहा गया है) संस्कृत छात्रवृत्ति (जिसे आगे योजना कहा गया है) प्रशासित कर रहा है जिसे माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अधीन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (जिसे आगे कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और, चूँकि योजना और इसके संबंध में जारी अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन, संस्कृत छात्रवृत्ति (जिसे आगे प्रसुविधा कहा गया है) राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों/सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन करने वाले अर्हित और प्रतिभाशाली छात्रों (जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है) को मौजूदा योजना मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान की जाती है;

और, चूँकि पूर्वोक्त योजना में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अतएव, अब, आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1— (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से आधार अधिप्रमाणन कराने या आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं समनुदेशित हुयी है, तो उससे नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी:

परन्तु यह कि यदि व्यक्ति बालक है तो आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग रजिस्ट्रारों से समन्वय और सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना करने या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधायें प्रदान करने सहित उपयुक्त उपायों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका नामांकन अभी तक नहीं हुआ है या जिनका आधार विवरण अद्यतन किया जाना है;

परन्तु यह कि ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या समनुदेशित किये जाने के समय तक, वह उक्त प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज, जिनका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय विधिमान्य हैं, प्रस्तुत कर अथवा यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे अभिप्रमाणन के लिए प्रदत्त या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु साक्ष्यित करने वाली सूचना उनकी तैयारी या अनुरक्षण से सम्बंधित प्राधिकारियों के डाटाबेस से इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो इस प्रकार प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, अर्थात्-

18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए, जिसे आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गयी है:

(क) नामांकन केंद्र में ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई नामांकन प्रक्रिया कराने वाले लाभार्थी की पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) सम्मिलित है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक यह साक्ष्यित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थात्:—

(2) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से उद्धरित है;

(3) भारतीय पासपोर्ट;

(4) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(5) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सम्बंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसके साथ रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(6) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(एक) यदि वह भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;

(दो) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(तीन) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(चार) यदि वह भारत का कार्डधारक, विदेशी नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक से भिन्न है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा होना चाहिये; या

तीन- माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके सम्बन्ध को साक्षित करने के लिए लाभार्थी की फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात:-

(एक) राशन कार्ड;

(दो) राजपत्रित अधिकारी जो तहसीलदार रैंक से अनिम्न राज्य सरकार का कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी हो, द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र;

(तीन) किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(चार) भारतीय पासपोर्ट;

(7) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(8) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सम्बंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसके साथ रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परीवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(9) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(एक) यदि वह भारत का कार्डधारक, विदेशी नागरिक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;

(दो) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(तीन) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(चार) यदि वह भारत का कार्डधारक, विदेशी नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक से भिन्न है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

नौ- ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक संरक्षक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षकत्व साक्षित करने के लिए अन्य दस्तावेज है, जो किसी विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या

दस- कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग विनिर्दिष्ट करे।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या नहीं समनुदेशित की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई नामांकन प्रक्रिया कराने वाले लाभार्थी की पावती, जिसमें ईआईडी सम्मिलित है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की फोटो हो, अर्थात:-

दस- भारत का चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

ग्यारह- राशन कार्ड;

बारह- राजपत्रित अधिकारी जो तहसीलदार रैंक से अनिम्न राज्य सरकार का कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी हो द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र;

तेरह- किसी सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

चौदह- भारतीय पासपोर्ट;

पन्द्रह- मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

सोलह- किसी सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

सत्रह- दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

अठ्ठारह- भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

उन्नीस- देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उसके साथ रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परीवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

बीस- किसी विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(एक) यदि वह भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;

(दो) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(तीन) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(चार) यदि वह भारत का कार्डधारक, विदेशी नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीज़ा अथवा वर्तमान में विधिमान्य अथवा समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीज़ा होना चाहिए; या

दस— ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक संरक्षक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षकत्व साक्षित करने के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

ग्यारह— कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग विनिर्दिष्ट करे:

(4) इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदाभिहित एक अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों या खंड (3) के अधीन उनकी विषयवस्तु को साक्षित करने वाली जानकारी के संबंध में जांच करेगा,

(क) myAadhar पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर EID जमा करके नामांकन अनुरोध की प्राप्ति, ताकि यह पुष्टि हो सके कि EID मान्य है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेज, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी ऐसे सरकारी निकाय या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को उनके साथ साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में अंतर्निहित जानकारी की तैयारी या अनुरक्षण से संबंधित हैं ।

2— लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधा प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग योजना के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ।

3— जहां किसी बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन पद्धति (अर्थात् फेसियल इमेज, फिंगर प्रिंट या आइरिस स्कैन आधारित अधिप्रमाणन) के माध्यम से किया गया किसी लाभार्थी के आधार संख्या का अधिप्रमाणन किसी भी कारण यथा, बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता से विफल हो जाता है, तो वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) यदि अधिप्रमाणन की कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित पद्धति सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन की कोई अन्य पद्धति या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणन, जहां भी संभव और ग्राह्य हो, प्रस्थापित किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित अधिप्रमाणन पद्धतियां संभव नहीं हैं, योजना के अधीन प्रसुविधायें यथास्थिति आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन कर आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात्, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दी जा सकती हैं:

(4) आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य या एम आधार एप का उपयोग कर सुलभ आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति) इसकी वास्तविकता आधार क्यूआर स्कैनर या एम आधार एप का उपयोग कर क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित किये जाने के पश्चात्।

(5) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य या इसके एम आधार एप का उपयोग करके सुलभ), इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस सम्बंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित किये जाने के पश्चात्।

4- उपर्युक्त में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, -

(क) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा से किसी बालक को वंचित नहीं किया जाएगा—

(एक) अधिप्रमाणन कराकर अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या धारित करने का प्रमाण देने में असफल रहने की स्थिति में; या

(दो) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में जहां उसे आधार संख्या नहीं समनुदेशित की गई है; और

(ख) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधा ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित कर और पैरा 1 के खंड (3) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट रीति से उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके सम्बंध को स्थापित कर दी जाएगी; और

(ग) जहाँ खंड (ख) के अधीन प्रसुविधा दी जाती है, उसी के संबंध में एक अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा, जिसकी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी।

5- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उनको देय प्रसुविधा से वंचित न हों, माध्यमिक शिक्षा विभाग डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर मिशन कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या डी-26011/04/2017-डी0बी0टी0 दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 (<http://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

6- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1735/XV-9-2025 dated October 17, 2025 :

No. 1735/XV-9-2025

Dated Lucknow, October 17, 2025

WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency ;

AND, WHEREAS the **Department of Secondary Education** (hereinafter referred to as the Department) in the Government of **Uttar Pradesh** (hereinafter referred to as the said Government) is administering **Sanskrit Scholarship** (hereinafter referred to as the Scheme) which is being implemented through the **Directorate of Secondary Education** (hereinafter referred to as the Implementing Agency) under the administrative purview of the **Department of Secondary Education**;

AND, WHEREAS under the Scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof, **Sanskrit Scholarship** (hereinafter referred to as the benefit) is given to the **qualified and talented students studying Sanskrit in Sanskrit schools/ colleges/ Sampurnanand Sanskrit University run in the State** (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines ;

AND, WHEREAS the aforesaid Scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of **Uttar Pradesh** ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act No. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of **Uttar Pradesh** hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the benefit under the Scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the **Department of Secondary Education** shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the **Department of Secondary Education** for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
- (b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—
 - (i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
 - (ii) Indian passport;

- (iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (v) In respect of a foreign national,—
 - I. if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - II. if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - III. if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - IV. if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
- (i) Ration card;
 - (ii) Caste certificate or Domicile certificate, issued by a Gazetted Officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;
 - (iii) Medical or insurance identity card issued by a Government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (iv) Indian passport;
 - (v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (vii) In respect of a foreign national,—
 - I. if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - II. if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - III. if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - IV. if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a Court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
 - (ix) Any other document as the **Department of Secondary Education** may specify.
- For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:*
- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—

- (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
- (ii) Ration card;
- (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;
- (iv) Medical or insurance identity card issued by a Government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (v) Indian passport;
- (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a Government entity or a public sector enterprise;
- (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
- (ix) Driving licence issued in India;
- (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (xi) In respect of a foreign national,—
 - I. if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - II. if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - III. if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - IV. if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a Court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xiii) Any other document as the **Department of Secondary Education** may specify.

(4) An officer designated by the **Department of Secondary Education** in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any Government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the benefits conveniently, the **Department of Secondary Education** shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the Scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan

based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

- (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
- (b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the Scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
 - (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the **Department of Secondary Education** or **Directorate of Secondary Education** for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

- (a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
 - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
 - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and
 - (b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
 - (c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the **Department of Secondary Education**.
5. In order to ensure that *bonafide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said Scheme, the **Department of Secondary Education** shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official *Gazette*.

By order,
PARTH SARTHI SEN SHARMA,
Apar Mukhya Sachiv.